श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमला

*35. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री अश्विनी कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय समुद्री क्षेत्र श्रीलंका की नौसेना द्वारा अब तक कितने तथा कब-कब भारतीय मछुआरे मारे गये, घायल किये गये और बन्दी बनाये गये ;

(ख) क्या मछुआरों को कोई चेतावनी दी गई थी, यदि हां, तो इनकी रक्षा करने में असफलता क्यों, कितनी बार और किन-किन तारीखों को हुई ; और

(ग) क्या श्रीलंका को इस बारे में कोई चेतावनी दी गई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 10 दिसम्बर, 1984 को एक भारतीय मछेरा मारा गया, दो 7 जनवरी, 1985 को तथा अन्य दो 13 जनवरी, 1985 को मारे गए । 1984 में गिरफ्तार भारतीय मछेरों की संख्या 175 थी । कई मछेरे घायल हुए थे ।

(ख) मछेरों को यह आम चेतावनी दी गई है कि वे भारतीय समुद्री सीमा से परे न जाए । सरकार ने भारतीय समुद्रों में अपने तट रक्षकों की उपस्थिति को सुदृढ़ किया है और इस क्षेत्र में नियमित गश्त की व्यवस्था की है ।

(ग) सरकार ने हमारे समुद्रों में श्रीलंका के नौ-पोतों द्वारा घुसपैठ और भारतीय मछेरों को परेशान करने तथा उनकी हत्या पर श्रीलंका की सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया । सरकार ने इनकी जान और माल की क्षति के लिए मुआवजा भी मांगा है ।

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Chairman, Sir, Indian fishermen are repeatedly attacked and killed in our own territorial waters. So, they have been deprived of their livelihood because they have stopped going for fishing nowadays. In his reply to my Unstarred Question on 24th January this year, the honourable Prime Minister stated that the Indian Coastguard has been patrolling the area to see that the fishermen are not put to any harassment. Sir, when on 13th February two persons were shot dead by Sri Lanka naval personnel, what happened? This has been reported in The Hindu dated 14th February: "The fishermen said the Coastguard or naval ships were not present anywhere near the spot when the two fishermen were shot dead by the Sri Lankan Navy. Therefore they demand additional Coastguard and naval vessels for patrolling and protecting fishermen." Sir, now regarding this joint patrollig, the Minister's reply is vague. Sir, adding insult to injury, the Sri Lankan Ministers who make seathing attack on India have made suggestions for joint patrolling. So, I would like to know from the Government whether the Government has expressed in no uncertain terms that India would never agree for any such joint patrolling.

Sir, had we shown some strong action, had we given ultimatum to the Sri Lankan Government, these repeated attacks would not have taken place. Sir, it is a challenge to the prestige and honour of India. I hope the Government of India will protect the Indian fishermen in our own territorial waters. Because the Government of India has miserably failed to protect our own fishermen, now they have announced a boat-march and also they are demanding arms to be supplied to themselves, defend themselves. So, I would like to know from the hon. Prime Minister what steps are going to be taken because even three days back again attacks have started on our fishermen.

MR. CHAIRMAN: Follow the two-minute rule.

SHRI V. GOPALSAMY: O. K., I am concluding, Sir.

So, this is going on repeatedly. So, I would like to know from the hon. Prime Minister what steps he has taken or he has proposed to take, whether any ultimatum will be given to the Sri Lankan Government to stop these attacks.

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: Sir, I have already mentioned that we have lodged a strong protest to the Sri Lankan Government and have conveyed the reaction of the Government of India about it in very clear terms, and they understand it very clearly now.

As regards providing protection, not only have our Coast Guards intensified their patrolling, put our Navy is also in touch with the Coast Guards. Besides, air surveillance has also been started from 24th February, 1985. I can assure the hon. Member that everything possible will be done to protect the life, honour and property of our fishermen.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Chairman, Sir, the serious problem of refugees is taking a very grave turn. Within twenty miles reach from our coast in Sri Lanka the terrific massacre and genocide of Tamils is taking place. Sir, the women and kids are being butchered and slaughtered. So, they are fleeing from their homes. So, giving doles or supplying clothes and food these things will not solve the problem. Unless we take a firm step, stand, this genocide will not stop. The refugees are everyday braving tumultuous seas and seeking sanctuary, they are coming everyday in hundreds and thousands.

So, Sir, I am very sorry to say, because of the callous attitude of India, because of the indifferent attitude of India, because of the low-key approach, because of the chicken-hearted approach of the Indian Government to the Sri Lankan problem, they dare to attack Tamils in Sri Lanka and they come into our territorial waters and attack our fishermen. Will the Government change this policy?

MR. CHAIRMAN: People will be interested in chicken.

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: Sir, I really do not know whether the hon. Member is a vegetarian or a non-vegetarian.

SHRI V. GOPALSAMY: This is not a matter to laugh at. Mr. Minister, I am very sorry, this is not a matter to laugh and ridicule.

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: Let me answer.

SHRI V. GOPALSAMY: When people are butchered, you are making jokes here. What is the joke? You must withdraw that.

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: Please listen. I have already mentioned that the Prime Minister made it very clear to the Security Minister of Sri Lanka who visited this country recently, and it was made very clear to him, that India is very concerned about what is happening in Sri Lanka and what the reaction and fall-out and repurcussions are in this country. Besides, this matter has also been raised twice in the U.N., and recently it has also been raised in the Human Rights Commission. Everything possible is being done to safeguard the interests of the Sri Lankan Tamilians. But, Sir. it would be realised that after all it is an internal matter of Sri Lanka, and whatever is possible, using our good offices and other means, we would continue to do, and the Government of India is very concerned about it. I would like to assure the hon. Member that we will continue to do it.

श्री शंकर सिह वाघेला : माननीय सभापति जी, एक ही प्रकार का जवाब सन रहा हूं राज्य सभा में या लोक मभा में एक दो माल से। The Government is giving the same reply. The Government is doing nothing.

रामायण के राम ने श्रीलंका के अन्दर आग नहीं लगाई बल्कि हमारी भारत सरकार की गलत नीतियां जो हैं इसने श्रीलंका में आग लगाई। हर रोज जो यहां

शरणार्थी आ रहे हैं इस के बारे में जो फिगर्स दी हैं वह भी गलत हैं। जवाब दिया है कि भारत सरकार पहुंचने वाले शरणार्थी जो हैं उनके आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। एक साल तक फिगर्स भी इट्ठी नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कब तक आप इस फिगर्स से इस हाउस को अवगत करायग ?

दूसरे सुविधा की जो बात कही गई है तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई सुविधा सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से नहीं है। मैं समझता हूं तमिलनाडु में ही सिर्फ शरणार्थी आ रहे हैं ऐसा नहीं है, शरनार्थी वहां से मार खा कर भी आ रहे हैं। कितनें ही शरणार्थी रास्ते में मारे गये। मैं जानना चाहता हूं आपने क्या-क्या सुविधाए उनको उपलब्ध कराई है और जो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई गई हैं उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ही इन्वाल्व है या सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी इन्वाल्व है ?

श्री खुर्शीद आलम खान : मान्यवर, मैंने बताया अपने जवाब में कि तकरीबन 50 हजार शरणार्थी आ चुके हैं। ऐसा अन्दाजा है कि पांच सौ शरणार्थी रोज रात को आ रहे हैं। फरवरी में जब से शरणार्थी आने शुरू हुए हैं उसकी फिगर्स हमारे पास है। 11 हजार 225 शरणार्थी आ चुके हैं। मैंने अपने जवाब में यह कहा है कि यह हमें नहीं मालूम कि 11 हजार 225 जो आए हैं वे कौन-कौन से दिन आए हैं। इसकी फिगर्स हम जमा कर रहे हैं। जहां तक उनको सुविधाएं देने का ताल्लुक है उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं—खाने की सुविधा, ठहरने की सुविधा। हर कोशिश यह की जा रही है कि जब तक हमारे देश में रहेंगे तब तक उनको पूरी सुविधाएं दी जाएं ताकि उनको तकलीफ कम रहे।

श्री शंकर सिंह वाघेला : शरणार्थी केवल तमिलनाडु में ही आ रहे हैं या दूसरे राज्यों में भी शरणार्थी आ रहे हैं और अगर दूसरे राज्यों में आ रहे हैं तो उनको क्या सुविधा दी जा रही हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खान : ज्यादातर जितने भी शरणार्थी आए हैं तमिलनाडु में आए हैं। लेकिन अगर और किसी दूसरे प्रदेश में आए हैं तो इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त यह इंफरमेशन मेरे पास नहीं है।

श्री अश्विनी कुमार : मान्यवर, श्रीलंका की समस्या सन् 1947 से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है। पिछले प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी वहां जा कर कुछ समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया और ऐसा लगता है कि विदेश नीति में श्रीलंका के बारे में हमारी नीति सर्वथा असफल रही है। हम वहां के जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनकी समस्या हल करने में सर्वथा असफल रहे हैं। उनकी नागरिकता की समस्या भी विचाराधीन है। पिछले दो वर्ष से जब से यह सरकार आई है श्रीलंका में तब से वहां पर जो भारतीय मूल के तमिल लोग थे उनके ऊपर अत्याचार किये है, अत्याचारों की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो शरणार्थी वहां से आ रहे हैं वे किस बुरी दशा में आ रहे हैं, किस बुरी आग में चल कर आ रहे हैं क्या आपने इसको देखा है? उनके घर जला कर उनको वहां से भेजा जा रहा है। वे जब वहां से आ जाते है तो वहां पर उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है। हर प्रकार से सारी तमिल पापुलेशन को श्रीलंका से व्हाइप आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ हमारा एक प्रश्न है जो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। इसमें हमारे मछुआरे भी पकड़े जा रहे हैं। ये हमारे देश के नागरिक हैं। जो वहां से आए हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि वे लंका में रहते थे और इस कारण उसमें हमारी रिस्पोंसिबिलिटी कम थी लेकिन जो हमारे मछुआरे जाते हैं उन पर भी आघात हो रहा है। हमें केवल इस पर बातचीत नहीं करनी चाहिये। पिछले दिनों में इजरायल ने, इंग्लैंड ने उनको हथियार दिये हैं, ट्रेनिंग दी है, हथियारों से लैस जहाज हिन्दुस्तान में उतर गया। उसको जाने की अनुमति केन्द्रीय सरकार ने दी है। क्या यह एक कारण नहीं है कि उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं। इस प्रकार से हथियार वहां पहुंचने से लंका को सहायता मिल रही है।

MR. CHAIRMAN: Allow the Minister to answer.

SHRI ASHWANI KUMAR: I am asking the question.

ये सारी जो घटनाएं हैं इसके कारण ही मछुआरों पर अत्याचार हो रहे हैं। दक्षिण भारत के जो हमारे मछुआरे हैं वे वहां पर मारे जा रहे हैं। इस सब को समाप्त करने के लिये आप क्या कंक्रीट स्टैप उठा रहे है? क्या हजारो लाखों लोग मरते चले जायेंगे और हम इसका निदान निकालने के लिये सरकार के वचन ही सुनते रहेंगे?

श्री खुर्शीद आलम खान : मान्यवर, मैंने बताया है कि न सिर्फ हम लोग सरकारी स्तर पर बातचीत कर रहे हैं बल्कि यू० एन० में भी यह सवाल आ चुका है और ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने भी यह सवाल है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस चीज की तरफ हमारा ध्यान नही है। हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जहां तक हमारे जो श्रीलंका में लोग थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में एक एग्रीमेन्ट हुआ था। उस वक्त 9 लाख 75 हजार ऐसे लोग थे जिनको श्रीलंका की सिटीजनशिप नहीं थी। इनमें से छः लाख लोगों को हमने हिन्दुस्तान में वापस लेने का वायदा किया जिनमें से 3 लाख 75 हजार श्रीलंका ने लेने का वायदा किया था। बाकी 1 लाख 78 हजार ऐसे हैं जिनके बारे में श्रीलंका ने फैसला ले लिया है। अभी 97 हजार ऐसे लोग बाकी हैं जिन्हें श्रीलंकन सिटीजनशिप देने के लिए श्रीलंका वालों को फैसला करना है। मगर चूंकि इस वक्त हालत ऐसे हैं जिनमें हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए पूरे तरीके से यह नहीं कहा जा सकता है कि उन 97 हजार में से कितनों को मिल गई है और कितनों को नही मिली है।

जहां तक जहाज के मामले का सवाल है, यह जहाज जरूर हमारे त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर उतरा था। जहाज को जो फ्लाइंग प्लान दिया जाता है उसमें उसको यहां नहीं उतरना था, लेकिन उसके पास फ्यूअल कम हो गया था, इस लिए जहाज को फ्यूअल कम होने की वजह से वहां उतरना पड़ा। उस जहाज को वहां उतरने के बाद वहां से जाने की इजाजत फ्लाइंग प्लान लेने के बाद जरूर दे दी गई।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इजाजत क्यों दे दी गई?

MR. CHAIRMAN: Miss Jayalalitha.

SHRI RAJIV GANDHI: Sir, I would like just to add one thing. No air craft landed here with any arms in it. There were no arms on board in any aircraft. There was one aircraft which had some ammunition. There is a difference between the two statements.

SHRI V. GOPALSAMY: That ammunition was meant to wipe out the Tamils. It was meant to kill the Tamils.

SHRI RAJIV GANDHI: It was not so marked.

SHRI V. GOPALSAMY: That ammunition was meant for killing Tamils.

MR. CHAIRMAN: The lady member is on her legs.

MISS JAYALALITHA: Sir, I am not arguing with India's foreign policy of non-interference in the internal affairs of another country, but where it involves the fishermen of our country, what is the use of our military might? How do we justify the enormous expenditure every year on defence if we do not utilise that military might to provide protection to our own citizens, the fishermen of Rameshwaram? How can the Government of India afford to allow any country, big or small, to get the impression that it can intrude with impunity into our territorial waters and attack and kill our citizens? A small island nation like Sri Lanka has the temerity and audacity to act like a hawk and intrude into and violate our maritime boundries and kill our citizens. And we act not like doves of peace but like lame ducks unable to fight back and defend ourselves.

What is the use of this military might if we do not utilise it to protect the lives of our own citizens? Why does not the Government of India, despite repeated attacks like this by the Sri Lankan Navy, give a proper military chastisement to Sri Lanka and teach them a lesson once and for all stop these attacks?

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: Sir, the hon. lady Member has said that we do believe in non-violence and non-interference in the affairs of another country. I can assure her that this is the policy no doubt, but at the same time, we have to provide protection to our fishermen and I have just mentioned that not only the Coast Guard has intensified the patrolling, but the Navy has also been alerted... (*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: Every day they are being attacked. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please allow him to finish.

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: Sir, let them finish. Then I will...

MR. CHAIRMAN: No, no. you finish and then they can go on.

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: Air surveillance is being done and the Navy has been alerted. All this has been done. As a result of this, we had arrested one of their vessels which intruded into our waters.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bhandare. last question

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Not only in India, but the entire world, are shocked at the gross violation of human rights in Sri Lanka and which have resulted in a large influx of refugees to our country. I am only on the question of joint patrolling. I think it is a death trap and we will be breaching the fundamental rule of international law of non-refoulement under which no refugee can be sent back unless he is assured protection of his personal life and liberty. I would, therefore, like to ask the honourable Minister as to what steps have been taken by our Government to ensure that the Sri Lankan army does not continue with its depredations.

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: This question has been raised in the UN Human Rights Commission and also the good offices of the Government of India are being utilised to tell them—Well, what is happening is having bad repercussions in this country.

MR. CHAIRMAN: Question Hour over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Directions to the State Governments for treating Tourism as Industry

*23. SHRI RAFIQUE ALAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have recently issued any directions to the State Governments to treat tourism as industry;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the response of the State Governments in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (c) the Approach Paper for the Seventh Five Year Plan approved by the National Development Council (NDC) in July, 1984 recommended that Tourism should be accorded the status of an Industry. The State Governments have accordingly been requested to declare tourism as an industry so that the concessions available to other industries also become applicable to Tourism The States of Meghalaya, West Bengal, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Orissa have already granted tourism the status of an industry.